वी.एस.टी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

कलेक्टर आॅफ सेंट्रल एक्साइज, हैदराबाद

8 जनवरी, 1998

[जे. एस. वर्मा, बी. एन. किरपाल और वी. एन. खरे, जे. जे.]

आबकारी कानूनः

केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1994 धारा 4-पहली अनुसूची विषय - 4.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियम, 1975 - नियम 5 ।

उत्पाद शुल्क-आकलन योग्य मूल्य का निर्धारण माल की बिक्री मूल्य पर प्राप्त ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा पर अनुमानित ब्याज का जोड़ - प्रतिभूति जमा लेने के बाद अपीलार्थी द्वारा ऋण सुविधा का लाभ उठाने वाले विक्रेता को कोई छूट नहीं दी गई - ऐसी जमाओं से प्रभावित नहीं होने वाली वस्तुओं का थेक मूल्य - माना गया कि, सभी आकलन योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बिक्री मूल्य में अनुमानित ब्याज नहीं जोड़ा जा सकता है।

अपीलार्थी सिगरेट के निर्माण और बिक्र्री का व्यवसाय कर रहा है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम,1944 पहले अनुसूची विषय संख्या 4 के तहत शुल्क के लिए आकलन योग्य है।

अपीलार्थी ने 22 सितंबर,1981 के परिपत्र के माध्यम से ऋण सुविधा योजना की शुरूआत की, बिक्री की जोखिम को पूरा करने के लिए उनके साथ ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा की गई थी। यह ऋण का विस्तार थोक ग्राहकों तक हुआ। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर ने 28 दिसंबर,1ः987 को अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाकि आकलन योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रतिभूति जमा पर 12

प्रतिशत अनुमानित ब्याज जोड़ा जा सके। जवाब मिलने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने अपीलार्थी के खिलाफ आदेश पारित किया। अपील पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के कलेक्टर ने सहायक कलेक्टर के आदेश के एक हिस्से को निरस्त कर दिया। आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपील को न्यायाधिकरण द्वारा यह मानते हुए अनुमति दी गई थी कि आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए अनुमानित ब्याज पर विचार किया जाना चाहिए।

न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने वाली इस अपील में अपीलकताओं ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा लिया गया थोक मूल्य प्रतिभूति जमा से प्रभावित नहीं था जो कुछ डीलरों ने किया था जो उधार पर माल प्राप्त करना चाहते थे। समान मूल्य सभी विक्रेताओं से लिया जाता था, चाहे वे कोई भी हो, इस तथ्य के साथ कि बिक्री नगद आधार पर की गई थी या ऋण के आधार पर । प्रत्यार्थी ने तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियम 1975 का नियम - 5, लागू होता है क्योंकि मूल्य एकमात्र विचार का प्रश्न नहीं था। ऐसी वस्तुओं का मूल्य, सकल मूल्य पर एवं अपीलार्थी द्वारा प्राप्त जमा प्रतिभूति पर अनुमानित ब्याज की राशि पर आधारित होना चाहिए।

अपल का अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

माना कि 1.) जब माल उधार पर बेचा जाता है और ब्याज प्राप्त होता है तो यह ब्याज उस कीमत का हिस्सा नहीं है जिस पर उत्पाद शुल्क देय है।

1.2 अतिरिक्त कलेक्टर का यह मानना सही था कि मूल्यांकन नियम का नियम-5 लागू नहीं होता है क्योंकि यह नहीं दिखाया गया था कि लिया गया मूल्य एकमात्र विचार का प्रश्न नहीं था। अपीलार्थी कंपनी के पास सभी विक्रेताओं को प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता केवल उन विक्रेताओं के लिए है जो ऋण सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन उन्हें कोई छूट नहींे मिलती है या कम कीमत का भुगतान करें, तो ऐसे मामले में उत्पाद शुल्क केवल बिक्रेताओं द्वारा भुगतान किए गए समान मूल्य पर ही लिया जा सकता है, बिना किसी अनुमानित ब्याज पर नहीं ।

1.3 . उत्पाद शुल्क भुगतान की गई कीमत पर माल के निर्माण पर हैं और वर्तमान मामले में भुगतान की गई कीमत सभी विक्रेताओं द्वारा समान हैं। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रतिभूति जमा की प्राप्ति पर सभी से शुल्क लिया जाता है और ऐसा कुछ भी दिखने को नहीं है कि प्रतिभूति जमा करने की स्थिति में विक्रेताओं से

कम कीमतें ली गयी हो। इस प्रकार, सभी विक्रेताओं से लिए जा रहे समान थोक मूल्य की अवहेलना करने और उक्त मूल्य में जमा प्रतिभूति के अनुमानित ब्याज के तत्व को केवल इसलिए जोड़ने का कोई औचित्य नहीं था सिर्फ इसलिए कि कुछ विक्रेताओं द्वारा पूर्व जमा ब्याज को कम कर दिया गया था।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम। इंडियन आॅक्सिजन लिमिटेड, (1988)36 ई.एल.टी.730 एस.सी. एवं भारत सरकार बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड (1995)77 ई.एल.टी. 433 एस.सी. ने इस पर भरोसा किया। ख्39 एफ.एच,

1.4 अपीलार्थी थोक विकेता से समान मूल्य वसूल रहा है। अगर बिक्री मूल्य में अंतर होता जैसे कि उदाहरण के लिए डिपॉजिट देने वाले डीलरों को विशेष छूट दी जाती तो यह कहना संभव होता कि दो अलग-अलग बाजार थे और दो अलग-अलग कीमतें और एक बाहरी प्रतिफल के लिए कम कीमत ली जा रही थी और ऐसे मामले में अनुमानित या वास्तविक ब्याज जोड़ा जा सकता था।

मेटल बॉक्स इंड लिमिटेड वी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, मद्रास, ख्1995, 2 एस.सी.सी.90,विशिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 1992 की सिविल अपील सं. 2524

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण,दिल्ली 1988-ए.के.ई/3234 में दिनंाकित 23.8.90 के निर्णय और आदेश सेः

अपीलार्थी की ओर से अनिल बी. देवन और एस. आर. सेतिया।

प्रतिवादियांे के लिए एन. के. बाजपेयी, पल्लव शिशोदिया और वी. के. वर्मा ।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधीश द्वारा दिया गया थाः

किरपाल, जे. इन अपीलों में निर्णय के लिए यह प्रश्न शामिल है कि क्या उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत ब्याज मुक्त जमा प्रतिभूति पर अनुमानित ब्याज पर विचार किया जाना चाहिए ताकि इसके तहत ऐसी प्रतिभूति जमाओं पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अनुमानित ब्याज को शामिल करके आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचा जा सके।

वी.एस.टी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सी.ए. नं0 2524/92 में अपीलार्थी) एक कंपनी है।

सिगरेट के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय पर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क की पहली अनुसूची की पूर्ववर्ती वस्तु संख्या 4 के तहत शुल्क के लिए आकलन योग्य था। और नमक अधिनियम,1944 । अन्य दो अपीलार्थी, वीनस टोबैको कंपनी प्राईवेट लिमिटेड है। लिमिटेड (सीए नंबर 2523/92 में अपीलार्थी) और हैदराबाद डेक्कन सिगरेट फैक्ट्री लिमिटेड(सीए नंबर 2611/92 में अपीलार्थी) भी सिगरेट निर्माता हैं और वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड(इसके वाद ''वीएसटी'' के रूप में संदर्भित) के लिए और उसकी ओर से सिगरेट बनाने के लिए अपने संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन अपीलों में शामिल प्रश्न, इसलिए, वी. एस. टी. के स्वामित्व वाले ब्रांड नाम के तहत निर्मित और बेची जाने वाली सिगरेट के आकलन योग्य मूल्य के निर्धारण से संबंधित है।

निर्विवाद तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित सिगरेट को थोक में, उत्पादन मूल्य, सह-शुल्क मूल्यों पर मुख्य विक्रेताओं को बेचा जाता है जो इन सिगरेटों को बिना किसी बिचैलिए के आधार पर खरीदते है। मुख्य विक्रेता सिगरेट को अन्य थोक विक्रेताओं को बेचते हैं जिन्हें उप-विक्रेता कहा जाता है जो बदले में इन सिगरेट को खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं। सिगरेटों को अपीलकर्ताओं द्वारा या तो नकद ले जाने के आधार पर या कुछ मुख्य विक्रेताओं को ऋण सुविधा प्रदान करके बेचा जा रहा था। जैसा कि अपीलकर्ता कंपनी, अर्थात, वी. एस. टी. ने पाया कि कई मुख्य विक्रेता सिगरेट के लिए भुगतान करने में काफी समय ले रहे थे, जो उन्हें वितरित किए गए थे, इसलिए उन्होने 22 सितंबर, 1981 को एक परिपत्र जारी किया, जिसके तहत कंपनी के साथ ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा किए जाने पर ऋण सुविधा की शुरूआत की गई। उक्त परिपत्र में यह लिखा गया था कि ''अपने ग्राहकों को इस तरह के ऋण की सुविधा प्रदान करने और अनुरूप जोखिम से खुद को बचाने के लिए आर क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक विक्रेताओं को अपनी सामान्य मासिक खरीद के लगभग 21 दिनों के बराबर कंपनी के पास प्रतिभूति जमा (ब्याज मुक्त) रखना होगा। यह पूरी तरह से मुख्य विक्रेताओं पर निर्भर है कि वे इस सुविधा के लिए अनुरोध करें और वैसे विक्रेता जो प्रतिभूति जमा नहीं करना चाहते हैं वे भुगतान के बदले डिलीवरी लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगें।

जमा प्रतिभूति राशि को इस्तेमाल करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित हैं। बकाया राशि या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए जो खरीदार को कंपनी या किसी

भी खाते में देय हो या यदि कंपनी द्वारा किसी भी खाते में खरीदार द्वारा कंपनी को देय किसी भी राशि की कटौती/समायोजन करने के बाद कोई शेष राशि बची है, खरीदार के साथ व्यापार बंद करने पर कंपनी प्रतिभूति जमा राशि वापस कर देगी और यह कंपनी के अन्य अधिकारों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगी।

सिगरेट के लिए बिक्री की संशोधित शर्तों की एक प्रति जो 1 अक्टूबर, 1981 से प्रभावी होगी, इसके साथ संलग्न किया गया है। क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने की आपकी इच्छा की स्थिति में कृप्या अपनी सुविधा के लिए संलग्न प्रपत्र के अनुसार एक पत्र भेजें।

अपीलार्थियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर का कार्यालय से दिनंाक 28 दिसंबर,1987 को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। उक्त सूचना में यह कहा गया था कि वी. एस. टी. द्वारा मुख्य विक्रेताओं से प्रतिभूति जमा की प्राप्ति और ब्याज का भुगतान किए बिना इन मुख्य विक्रेताओं की सिगरेट की बिक्री मूल्य को प्रभावित करेगा। तदनुसार मुख्य विक्रेताओं से वी. एस. टी. द्वारा प्राप्त प्रतिभूति जमा राशि पर 12 प्रतिशत की दर से एक अनुमानित ब्याज तैयार करने और इसे सिगरेट के बिक्री मूल्य में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था ताकि उपरोक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा स्वीकृत सिगरेट के लिए देय आकलन योग्य मूल्य के साथ-साथ अंतर शुल्क को फिर से निर्धारित किया जा सके। यह इस आधार पर प्रस्तावित किया गया था कि वीएसटी डीलरों द्वारा सिगरेट का बिक्री मूल्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 4 के तहत सामान्य मूल्य नहीं है और ऐसी स्थिति में जहां संबंधित पक्षों के बीच अतिरिक्त मूल्य प्रतिफल पर विचार किया गया है, सामान्य मूल्य केवल मूल्यांकन नियम,1975 के नियम 5 के तहत निर्धारित किया जाना था। उक्त कारण बताओं नोटिस में अपीलार्थियों द्वारा माल ढुलाई सेवा शुल्क वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रसीद का भी उल्लेख किया गय, लेकिन इन अपीलों में हम उस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

आबकारी प्राधिकरण के दावे का खंडन करते हुए उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब भेजा गया था। वी. एस. टी.. ने अपनी दावेदारी से इनकार करते हुए रूपये की मांग के अनुसार विरोध दर्ज करते हुए 2,23,10, 405.79 रूपये का भुगतान किया। अन्य दो अपीलार्थी, अर्थात् वीनस टोबैकों कंपनी प्रा. लिमिटेड और हैदराबाद डेक्कन सिगरेट फैक्ट्री लिमिटेड ने भी इसी तरह विरोध दर्ज करते हुए क्रमशः रू

3,92,864.89 और रू 18,84, 718.74 रूपये का भुगतान किया।

17 मार्च,1988 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने एक अधिनिर्णय पारित आदेश पारित किया जिसमें वी. एस. टी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरूद्ध रू 2,23,10, 405.79 की मांग की पुष्टि की। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित सहायक कलेक्टरों द्वारा अन्य दो अपीलार्थियों के खिलाफ भी इसी तरह के आदेश पारित किए गए थे। इसके बाद इन सभी तीन अपीलकताओं ने अपील दायर की। केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के कलेक्टारों ने 19 अगस्त, 1988 को एक आदेश पारित किया, जिसके तहत उन्होंने सहायक कलेक्टर, उत्पाद शुल्क के आदेश के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसमें निर्धारणीय मूल्य में जमा प्रतिभूति पर अनुमानित ब्याज जोड़ने की मांग की गई थी, जबकि इसके अतिरिक्त माल ढुलाई सेवा शुल्क होने की पुष्टि की गई थी।

आबकारी अधिकारियों ने तब आकलन योग्य मूल्य से अनुमानित ब्याज हटाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने अनुमति दी। विभाग की अपील में कहा गया है कि सिगरेट के आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए अनुमानित ब्याज शुल्क पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के अतिरिक्त वाणिज्यिक प्रतिफल को मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए न कि आकलन योग्य मूल्य में। न्यायाधिकरण के इस फेसले के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है।

अपीलार्थियों की ओर से यह श्री अनिल ठण् क्पअंद द्वारा तर्क दिया गया था,

विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थियों द्वारा लिया गया थोक मूल्य किसी भी तरह से उस प्रतिभूति जमा से प्रभावित नहीं था जो कुछ विक्रेताओं ने की थी जो माल को ऋण पर प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विक्रेताओं के साथ लेन-देन बिना किसी बिचैलिए के आधार पर होता था और अपीलकर्ता सभी विक्रेताओं से एक समान मूल्य लेते थे, इस तरह की परवाह किए बिना कि बिक्री नकद आधार पर की गई थी या ऋण पर। उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड एवं सीमा शुल्क द्वारा जारी दिनांक 27 मई,1996 को जारी नवीनतम परिपत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि विधि मंत्रालय ने सलाह दी थी कि यदि थोक खरीदार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा/अग्रिम राशि और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बीच कोई संबंध नहीं है या यदि विभाग

अतिरिक्त प्रतिफल का मुद्रा मूल्य निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन)नियम,1975 के नियम 5 के प्रावधान लागू नहीं होंगें। परिपत्र में आगे कहा गया है कि आम तौर पर ''जहां एक ही कीमत उन खरीदारों से ली जाती है जिन्होंने जमा किया है और जिन्होंने जमा नहीं किया है और/या जहां अग्रिम विशुद्ध रूप से एक प्रतिभूति जमा है और इस तरह की जमा राशि द्वारा अर्जित ब्याज खरीदार को जमा किया जाता है, ऐसे अग्रिम पर अनुमानित ब्याज की कीमत नहीं जोड़ा जा सकता है''।

उपरोक्त निवेदन का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वकील श्री एन. के. बाजपेयी, ने तर्क दिया कि अपीलकताओं ने ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा प्राप्त करके काफी आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इस जमा की प्राप्ति को आकलन योग्य मूल्य निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानियम 5 लागू होता है क्योंकि मूल्य एकमात्र विषय नहीं था और ऐसी वस्तुओं का मूल्य अपीलार्थियों द्वारा प्राप्त जमा प्रतिभूति पर मूल्य और अनुमानित ब्याज की राशि के कुल मूल्य पर आधारित होना चाहिए। अपने निवेदन के समर्थन में मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, मद्रास, ख्1952, 2 एसी. सी. सी. 90 के मामले में इस न्यायालय के फेसले पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी।

मेटल बॉक्स के मामले में निर्णय लेने से पहले यह उचित होगा कि उन अन्य निर्णयों का उल्लेख करना जो इस मुद्दे पर प्रासंगिक है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम इंडियन आॅक्सीजन लिमिटेड, (1988) 36 ई. एल. टी. 730 एस. सी. और भारत सरकार बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड, (1995) 77 ई. एल. टी. 433 एस. सी. । भारतीय आॅक्सीजन मामले में दो प्रश्न जो विचार के लिए उठे थे, वे थे कि क्या गैस सिलेंडरों के लिए किराया शुल्क और गैस सिलेंडरों के कई रिटर्न के कलए जमा किए गए ब्याज, चाहे ब्याज अनुमानित हो या वास्तवकि, को आकलन योग्य मूल्य निर्धारित करने में शामिल किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

"यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अधिनियम के तहत शुल्क, निर्माण पर है।

अधिनियम की धारा 4(1) (ए) के तहत किसी भी वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मूल्य के संदर्भ में उत्पाद शुल्क योग्य माल, ऐसा मूल्य, निम्नलिखित के अधीन होगा-

इस धारा के अन्य प्रावधानों को समामन्य मूल्य माना जाएगा। अर्थात् ऐसी कीमत जिस पर ऐसी वस्तुएं निर्धारित द्वारा थोक व्यापार के दौरान एक खरीदार को सामान्य रूप से बेचा गया हो, उस समय और स्ाान पर डिलीवरी देना या हटाना, जहां खरीदार संबंधित व्यक्ति नहीं है और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है। यहां बिक्री गैसों की है। यह शुल्क गैसों के निर्माण पर है। और ये गैसें उत्सर्जनीय वस्तुएं हैं।

यह माना गया कि गैस सिलेंडरों की आपर्ति गैसों की आपूर्ति के लिए सहायक थी। यह ग्राहकों के लिए अपने स्वयं के सिलेंडर लाने की स्वतंत्रता थी और ऋण देने की आवश्यकता केवल तभी दिया जाना आवश्यक था जब ग्राहकों द्वारा कंपनी से सिलेंडर की मांगकी गयी। सिलेंडर देने की इस गतिविध्या को सहायक माना जाता था और इस तरह से प्राप्त जमा से लाभ और लाभ को उत्पाद शुल्क योग्य मुख्य वस्तुओं के मूल्य की गणना करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता नहींे थी। राजस्व की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि खरदारों के दो अलग अलग वर्ग थे; ऐसे खरीदारों में से एक वर्ग वह था जो अपने सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे और दूसरे जो गैसों की आपूर्ति आपूर्तिकताओं के सिलेंडर से प्राप्त करते थे। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि विभिन्न दरों के लिए खरीदारों के इन दो वर्गों ने दो अलग अलग बाजारों का गठन किया जो धारा-4 के तहत अनुमेय थे। इस विवाद से निपटने के लिए इसे पृष्ठ 732 पर इस प्रकार देखा गया थाः

"विभिन्न वर्गों के लिए खरीदारों के विभिन्न वर्ग हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 4(1)(
ए) इस बात पर जोर देती है कि यदि माल का प्रकार एक समान है, किमतें भी समान होनी चाहिए। उक्त खंड यह अभिनिर्धारित करता है कि जहां सामान्य अभ्यास के अनुसार ऐसा सामान, अर्थात गैसों को विभिन्न वर्गों के खरीदारों को बेचा जाता है। अगर गैसों को अलग अलग लागों को बेचा गया होता अलग - अलग कीमतें ली जा सकती हैं। विभिन्न दरों पर खरीदारों के अलग अलग वर्ग हो, यह संभव है कि वहां अलग अलग बाजार हो सकता है लेकिन यहां सिलेंडर का किराए जैसे शुल्क संबद्ध

सेवाएं हैं और निर्माण की गतिविधि नहीं है। इसलिए धारा 4(1)(ए) का प्रावधान राजस्व के लिए कोई लाभप्रद नहीं हो सकता है।
(अवधारण)

मद्रास रबर फैक्ट्री मामले (उपर) में इस न्यायालय ने धारा 4 का विश्लेषण किया और निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

"यह स्पष्ट है कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य के उद्देश्य के लिए धारा 4 की उप-धारा (1) आमतौर पर सामान्य मूल्य जिस पर ऐसी वस्तु बेची जाती है, अर्थात धारा 4 की उप-धारा (1), के खंड (ए) के तहत। केवल वहां जहां माल नहीं बेचा जाता है और जहां ऐसी वस्तुओं की सामान्य कीमत कुछ लोगों के लिए निर्धारित नहीं की जा सकती है या ऐसी वस्तुओं की कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता है या ऐसी स्थिति में नहीं है उस परिस्थिति मंे अन्य कारण के साथ खंड (ख) आकर्षित किया गया है, जिसके तहत निकटतम निर्धारणीय समतुल्य मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उस संबंध में बनाए गए नियम - खंड (बी) एक अवशिष्ट की प्रकृति मंे है। इसलिए, खंड (बी) का सहारा वहां लिया जाना चाहिए जहां सामान्य मूल्य नहीं हो सकता है उसमें वर्णित कारणों का पता लगाया गया है। दूसरे शब्दों में, जहाँ सामान्य मूल्य कीमत उपलब्ध है या पता लगाने योग्य है, खंड (बी) का सहारा लें, इसकी अनुमति नहीं है''।

इसके बाद इस बात पर विचार किया गया कि प्राप्त मूल्य से कौन सी विभिन्न कटौती जो आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए अनुमेय थीं। निर्माता द्वारा प्राप्त राशि से कटौती के रूप में दावा की गई राशि में से एक क्रडिट पर बेचे गए समान पर उसके द्वारा प्राप्त ब्याज का तत्व था। इस पर विचार करते हुए न्यायालय ने पृष्ठ 470 पर निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"निर्धारिती (मद्रास रबर फैक्ट्री) का मामला यह है कि जहां थोक खरीदारों को बेचा जाता है और भुगतान कुछ समय बाद प्राप्त किया जाता है, यह वास्तव में ऋण पर बिक्री का मामला है और, इसलिए, माल की डिलीवरी की तारीख से लेकर अब तक का ब्याज इसकी कीमत की प्राप्ति की तारीख से कटौती की जानी चाहिए। माल का मूल्य। प्रभारित ब्याज, कवल भुगतान करने में लगने वाले समय के बदले में थोक

खरीदार से लिया जाता है। चुँकि यह बाद में प्राप्त राशि है डिपो से बिक्री और बॉम्बे टायर इंटरनेशनल में शामिल किसी भी दायरे में नहीं आता है, यह स्पष्ट रूप से है बाह्य है। इसलिए इस कटौती के दावे की अनुमति है।

उपरोक्त टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि जब माल उधार पर बेचा जाता है और ब्याज प्राप्त होता है जो उस मूल्य का हिस्सा नहीं है जिस शुल्क देय है और जिसपर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता अपने थोक विक्रेताओं से एक समान मूल्य ले रहे हैं। कीमत जिस पर उत्पादन मूल्य पर सिगरेट बेची जाती है, वह समान थी, चाहे नकद बेचीं गयी हो उधार, कोइ भी हो। जैसा कि परिपत्र में संकित दिया गया है और इसमें कोई विवाद नहीं है। उसमें क्या कहा गया है कि वाणिज्यिक प्रतिफल में से एक ब्याज मुक्त जमा योजना शुरू करना ऋण बिक्री के जोखिम को पूरा करने के लिए था। जो थोक ग्राहकों तक विस्तारित था। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन बिक्री के संबंध में भी बिक्री मूल्य का नकद के खिलाफ और ऋण पर नहीं निर्धारण की गई थी। अगर बिक्री मूल्य कोई अंतर होता जहां उदाहरण के लिए, विशेष छूट दी गई थी उन बिक्रेताओं को जिन्होंने जमा राशि दी थी, हो सकता है कि वे कहें कि दो अलग अलग बाजार थे और दो अलग अलग कीमतें थीं और वह कम कीमत थी एक बाहरी प्रतिफल के लिए आरोपित किया जा रहा था और, ऐसे मामले में अनुमानित या वास्तविक ब्याज जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। मेटल बॉक्स केस (ऊपर) में दो अलग-अलग कीमतें ली जा रही थीं।

मेटल बॉक्स के मामले में निर्धारिती उन वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे जिनकी पेशकश की गई थी। मेसर्स पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड, एक थोक खरीदार को बिक्री के लिए, जिसे अपने सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के विपणन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्मित कंटेनरों के बड़े हिस्से की आवश्यकता थी। एक स्थित और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड ने बड़ी राशि अग्रिम के तौर पर दी। पक्षों के बीच एक समझौता किया गया था जिसके

परिणामस्वरूप निर्धारिती पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड द्वारा छूट दी गई थी जिसे सकल मूल्य से काटा जाना था। आबकारी अधिकारियों और न्यायाधिकरण द्वारा इस कटौती की अनुमति नहीं दी गई थी। इस न्यायालय में निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण ने पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारिती को दिए गए अग्रिम पर तदर्थ द्वारा खीद मूल्य की लोडिंग को बहाल करने में गलती की। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने ध्यान दिया कि तथ्य यह है कि पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड एक थोक खरीदार था जो अपीलार्थी के कुल उत्पादन का नब्बे प्रतिशत उठा रहा था। निर्धारिती पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड को सामान्य मूल्य से पचास प्रतिशत की छूट दे रहा था और पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड ने निर्धारिती की बड़ी मात्रा में ब्याज मुक्त राशि दी थी। इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड से अपीलार्थी द्वारा ली गई कीमत को पात्रों की सामान्य कीमत नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, दिए गए अग्रिमों पर अनुमानित ब्याज पर ध्यान में रखते हुए विभाग की कार्रवाई को बरकरार रखा गया।

मेटल बॉक्स केस स्पष्ट रूप से अलग है। प्रतिभूति के रूप में दी गई राशि वर्तमान मामलों में जमा प्रतिभूति 21 दिनों की आपूर्ति के मूल्य को दर्शाता है जबकि मेटल बॉक्स मामले में बड़ी मात्रा में धन अग्रिम दिया गया था। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेटल बॉक्स मामले में करनिर्धारक मेंटल बॉक्स ने पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड को उसके सकल बिक्री मूल्य पर पचास प्रतिशत छूट दी थी और इस तरह अन्य खरीदारों से लिए गए मूल्य की तुलना में कम मूल्य लिया था। वर्ममान मामले में सिगरेट उत्पादन मूल्य पर थोक विक्रेताओं को बेची जाती है। समान मूल्य पर विक्रेता इस तथ्य की परवाह किए बिना कि खरीदार उधार पर सिगरेट खरीद रहा है या नकद में पैसे का भुगतान कर रहा है।

उत्पाद शुल्क, जैसा कि निर्धारित किया गया है, माल के निर्माण पर है। वर्तमान मामले में सभी विक्रेताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत समान हैं यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन डीलरों को कोई विशेष ध्यान दिया गया था जिन्होंने प्रतिभूति जमा दी थी। न ही किसी दस्तावेज या आंकड़े के संदर्भ में यह दिखाया गया है कि इस तरह की जमा राशि की प्राप्ति के कारण सभी खरीदारों से ली जाने वाली कीमत में कमी की गई थी। केवल इसलिए कि कुछ विक्रेताओं से पूर्व-जमा ब्याज कम किया गया था, उत्पाद शुल्क अधिकारियों और न्यायाधिकरण द्वारा इस निष्कर्ष इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके बाद भारतीय आॅक्सीजन और मद्रास रबर फैक्ट्री के मामलों (ऊपर) में भी निर्णय लिए गए। इस प्रकार समान थोक मूल्य के

संबंध, जबकि सभी विक्रेताओं से समान रूप से कीमत ली जा रही थी और उक्त मूल्य में प्रतिभूति जमा के अनुमानित ब्याज के तत्व को जोड़ा जा रहा था, इसका कोई औचित्य नहीं था।

हमारी राय में अतिरिक्त कलेक्टर का यह निष्कर्ष निकालना कि मूल्यांकन नियमों का नियम-5 वर्तमान मामला में लागू नहीं हटा है, सही था, क्योंकि यह नहीं दिखाया गया था कि ली गई कीमत एकसामन नहीं थी। जब अपीलकर्ताओं द्वारा सभी विक्रेताओं को प्रतिभूति जमा देने की आवश्यकता होती है जो ऋण सुविधाओं का लाभ उठाते हैं लेकिन कोई छूट नहीं मिलती है या कम राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो ऐसे मामले में उत्पाद शुल्क केवल डीलरों द्वारा किये गये एकसमान भुगतान पर लगाया जा सकता है, बिना किसी अनुमानित ब्याज के विक्रेताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत पर।

उपरोक्त कारणों से अपीलों की अनुमति दी गई। सी.ई.जी.ए.टी. के आदेश को निरस्त किया जाता है और प्रतिवादी की ओर से अतिरिक्त मांग के सम्बन्ध में जारी कारण बताओं नोटिस को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थियों को मूल्य का अधिकार होगा।

अपील स्वीकृत